
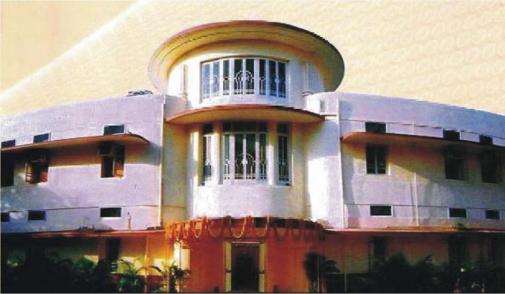


UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

GS Paper - II : SOCIAL JUSTICE



Dr. S. S. Pandey



UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

2

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन - I
(200 अंक / 2 घण्टा)

सामान्य अध्ययन - II
(200 अंक / 2 घण्टा)
(केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक)

मुख्य परीक्षा

A. सामान्य अध्ययन - 1000 अंक

- सामान्य अध्ययन - I (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - II (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - III (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - IV (250 Mark 3Hrs.)

B. वैकल्पिक विषय - 500 अंक

- वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र - I (250 Mark 3Hrs.)
- वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र - II (250 Mark 3Hrs.)

C. निबंध

D. अनिवार्य विषय - 600 अंक
(केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक)

- अनिवार्य : अंग्रेजी (300 Mark 3Hrs.)
- अनिवार्य : भारतीय भाषा (300 Mark 3Hrs.)

साक्षात्कार

275 अंक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन

3

सा. अध्ययन-I (250 Marks 3 hrs.)

- भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास
- भारतीय समाज
- भारत एवं विश्व का भूगोल

सा. अध्ययन-II (250 Marks 3 hrs.)

- शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली
- सामाजिक न्याय
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सा. अध्ययन-III (250 Marks 3 hrs.)

- आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- जैव-विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
- आंतरिक सुरक्षा

सा. अध्ययन-IV (250 Marks 3 hrs.)

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूढ़ि

GENERAL STUDIES PAPER - II

4

Dr. S. S. Pandey

सामाजिक न्याय

SOCIAL JUSTICE

GS Paper - II (UPSC : Syllabus)

5

Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations.

- Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.
- Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.
- Separation of powers between various organs dispute redressal mechanisms and institutions.
- Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries.
- Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.
- Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary—Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity.

6

- Salient features of the Representation of People's Act.
- Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies.
- Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.
- Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
- Development processes and the development industry—the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.
- Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.
- Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.
- Issues relating to poverty and hunger.

7

- Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance-applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.
- Role of civil services in a democracy.
- India and its neighborhood- relations.
- Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.
- Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.
- Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate.

Social Justice (UPSC : Syllabus)

8

- Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.**

सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

- The role of NOGs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders in development processes and the development industry.**

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में गैर - सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

- Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.**

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

11

- **Issues related to development and management of Social Sectors/Services relating to Health, Education, Human Resources.**

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

16

3. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से **लैंगिक न्याय** के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws. (Answer in 250 words) 15

12

- **Issues related to poverty and hunger and developmental issues.**

गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय एवं विकासात्मक मुद्दे।

17

4. "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

"Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer. (Answer in 250 words) 15

13

UPSC - CSE - 2023
पूछे गए प्रश्न - 06/80

18

5. विभिन्न क्षेत्रों में **मानव संसाधनों** की आपूर्ति में वृद्धि करने में **कौशल विकास कार्यक्रमों** ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment. (Answer in 250 words) 15

14

1. **मानव संसाधन विकास** पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. (Answer in 150 words) 10

19

6. भारत में राज्य विधायिकाओं में **महिलाओं** की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. (Answer in 250 words) 15

15

2. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत की **प्रतिस्पर्धा आयोग** की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions. (Answer in 150 words) 10

20

UPSC - CSE - 2022
पूछे गए प्रश्न - 06/75

21

1. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Gati-Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. (Answer in 150 words) 10

22

2. दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 remains only a legal document without intense sensitisation of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. (Answer in 150 words) 10

23

3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

Reforming the government delivery system through the Direct Benefit Transfer Scheme is a progressive step, but it has its limitations too. Comment. (Answer in 150 words) 10

24

4. कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss. (Answer in 250 words) 15

25

5. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अधिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. (Answer in 250 words) 15

26

6. स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse. (Answer in 250 words) 15

27

UPSC - CSE - 2021

पूछे गए प्रश्न - 06/75

28

1. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

"Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development." Analyze. (Answer in 150 words) 10

29

2. "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

"Earn while you learn" scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful." Comment. (Answer in 150 words) 10

30

3. क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with examples. (Answer in 150 words) 10

31

4. क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification. (Answer in 250 words) 15

32

5. "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आन्दोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

"Though women in post-Independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal." Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? (Answer in 250 words) 15

33

6. क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenges of this alternative model. (Answer in 250 words) 15

34

UPSC - CSE - 2020

पूछे गए प्रश्न - 05/70

35

1. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिए। 10

In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss. 10

36

2. एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तीकरण को और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। 15

Which steps are required for constitutionalisation of a Commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. 15

37

3. "केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है।" इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। 15

"The incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone". In this context analyse the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report. 15

38

4. "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है।" 'स्वयं सहायता समूहों' की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। 15

"Micro-Finance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India". Evaluate the role of 'Self-Help Groups' in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. 15

39

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। 15

National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient the education system in India. Critically examine the statement. 15

40

UPSC - CSE - 2019

पूछे गए प्रश्न - 07/90

41

1. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। 10

Despite Consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. 10

46

6. विभिन्न सेवा क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए 15

The need for cooperating among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of 'collaboration' and 'team spirit'. In the light of statements above examine India's development process. 15

42

2. भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूत कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। 10

There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items squeezing their food-budget - Elucidate. 10

47

7. सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। 15

Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss. 15

43

3. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। 10

Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based Projects / Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. 10

48

UPSC - CSE - 2018

पूछे गए प्रश्न - 06/75



44

4. "स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृवंशात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।" टिप्पणी कीजिए। 15

"The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process." Comment. 15

49

1. "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

"Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment." Comment with relevant illustrations. (Answer in 150 words) 10

45

5. "विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।" चर्चा कीजिए। 15

"In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages." Discuss. 15

50

2. भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वपेक्षा है। व्याख्या कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

Appropriate local community level healthcare intervention is a prerequisite to achieve 'Health for All' in India. Explain. (Answer in 150 words) 10

51

3. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? (Answer in 250 words) 15

52

4. समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरापन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

The multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case. (Answer in 250 words) 15

53

5. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

How far do you agree with the view that the focus on the lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India? (Answer in 250 words) 15

54

6. 'भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद, निर्धनता अभी भी विद्यमान है।' कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10

"Despite implementation of various programmes for eradication of poverty by the government in India, Poverty is still existing." Explain by giving reasons. (Answer in 150 words) 10

55

UPSC - CSE - 2017
पूछे गए प्रश्न - 06/75



56

1. "जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।" 'वाश' योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

"To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs, the identification of beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes." Examine the statement in the context of the WASH scheme.

57

2. क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए।

Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.

58

3. अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए।

Hunger and Poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement.

59

4. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer.

60

5. "वर्तमान समय में स्वयं-सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परन्तु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए।

"The emergence of Self Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities". Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.

61

6. “भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है।” भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

“Poverty Alleviation Programmes in India remain mere show pieces until and unless they are backed by political will”. Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India.

66

3. ‘ट्रान्स्पैरेन्सी इण्डरनेशनल’ के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है।

In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India.

62

UPSC - CSE - 2017 : पूछे गए प्रश्न (GS Paper-I)

7. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गयी दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (150 शब्द)

What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs)?

67

4. क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है?

Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change?

63

UPSC - CSE - 2016

पूछे गए प्रश्न - 07/87.5

68

5. “पारम्परिक अधिकारीतंत्र संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।” टिप्पणी कीजिए।

“Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio economic development in India.” Comment.

64

1. प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं?

Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?

69

6. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए।

Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.

65

2. “विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योयाश्रित होती है।” भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए।

“Effectiveness of the government system at various levels and people’s participation in the governance system are interdependent.” Discuss their relationship in the context of India.

70

7. “भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।” सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार-योग्य बनाने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं?

“Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative.” What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?

UPSC - CSE - 2016 : पूछे गए प्रश्न (GS Paper-I)

71

8. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए।

Why are the Tribals in India referred to as the Scheduled Tribes? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their Upliftment.

72

UPSC - CSE - 2016

पूछे गए प्रश्न - 06/75



73

1. विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम (एफ. सी.आर.ए.), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Examine critically the recent changes in the rule governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.

74

2. आत्मनिर्भर समूह (एस.एच.जी.) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस.बी.एल.पी.), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

The Self Help Group (SHG) Bank Linkage Program (SBLP), which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programme. Elucidate.

75

3. पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाधकताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।

How can be the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the Environment? Discuss throwing light on the major constraints.

76

4. भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा?

The quality of higher education in India requires major improvement to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of technical and higher education in the country. Discuss.

77

5. "सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएँगे?"

Public health system has limitation in providing universal health coverage. Do you think that private sector can help in bridging the gap? What other viable alternatives do you suggest?

78

6. यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किए गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty over time. Do you agree. Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators.

79

UPSC - CSE - 2014

पूछे गए प्रश्न - 05/62.5



80

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए।

The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing sociocultural hurdles. Examine.

81

2. क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती है।

Do government's schemes for up lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economics?

86

1. मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरंभ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रान्त (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

The concept of Mid Day Meal (MDM) scheme is almost a century old in India with early beginnings in Madras Presidency in pre independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last two decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success.

82

3. खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बाँछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके प्रोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए।

An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation's glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

87

2. स्वयं सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाईयों का, एक अवधारणा की सतत सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए।

The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the microfinance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss.

83

4. क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए।

Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.

88

3. केन्द्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

The Central Government frequently complains on the poor performance of the State Governments in eradicating suffering of the vulnerable sections of the society. Restructuring of Centrally sponsored schemes across the sectors for ameliorating the cause of vulnerable sections of population aims at providing flexibility to the States in better implementation. Critically evaluate.

84

5. सरकार की दो समान्तर चलाई जा रही योजनाओं यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एनपीआर.) एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिए।

Two parallel run schemes of the Government viz. the Adhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.

89

4. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए।

The basis of providing urban amenities in rural areas (PURA) is rooted in establishing connectivity. Comment.

85

UPSC - CSE - 2013

पूछे गए प्रश्न - 06/60

90

5. उन सहस्रवर्षिक विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए।

Identify the Millennium Development Goals (MDGs) that are related to health. Discuss the success of the actions taken by the Government for achieving the same.

91

6. यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों के नागरिकों के घोषणा-पत्र (चार्टर) बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

Though Citizen's charters have been formulated by many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizens' satisfaction and quality of services being provided. Analyse.

96



Dr. S. S. Pandey

Social Justice & Development

सामाजिक न्याय एवं विकास

92



Dr. S. S. Pandey

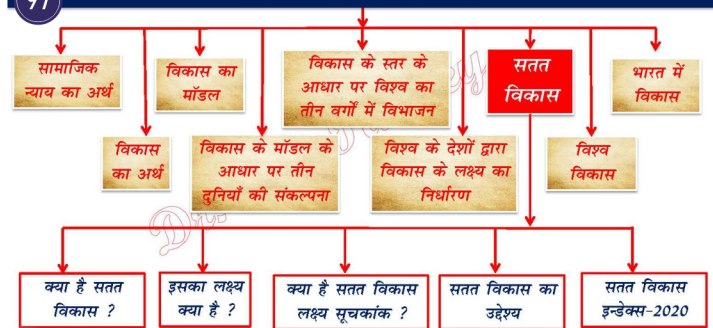
सामाजिक न्याय (Social Justice)

Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors and Issues Arising out of their Design and Implementation.

सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

97

सामाजिक न्याय एवं विकास



KGS



IAS